भारत सरकार/Government of India
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
Ministry of Finance, Department of Revenue
सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय
Office of the Commissioner of Customs (Preventive)
110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय
110 Mahatma Gandhi Road, NER,Shillong – 793001, Meghalaya
फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007.ई–मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

(हिंदी अनुवाद)

जन सूचना संख्या - 04/2017

शिलांग दिनांक 4 जुलाई 2017

विषय: निर्यात प्रक्रिया और कंटेनरयुक्त कार्गो के सीलिंग - संबंधि

दिनांक 01.07.17 के सीबीईसी परिपत्र सं। 26/2017 - सीमा शुल्क द्वारा प्रतिपादित संशोधित प्रक्रिया और कंटेनरकृत कार्गो की सीलिंग में सभी संबंधित का ध्यान आकर्षित किया जाता है जो नीचे दिया गया है:

1. दिनांक 01-07-2017 से वस्तु और सेवा कर परिचालित हो गया है। जीएसटी शासन में, निर्यात से संबंधित शासकीय प्रावधान एकीकृत वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 (आईजीएसटी अधिनियम) की धारा 16 में निहित हैं। निर्यात के लिए वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति को "शून्य रेटेड सप्लाई" के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसका अर्थ यह है कि कर भुगतान की वापसी के प्रावधान के साथ एकीकृत कर के भुगतान के बिना माल को बॉन्ड या उपक्रम के पत्र के तहत निर्यात किया जा सकता है।

2. जीएसटी की शुरुआत के साथ, माल के निर्यात से संबंधित मौजूदा प्रक्रियाएं जैसे कि छूट / धनवापसी का दावा, वेयरहाउस या किसी अन्य स्थान पर कंटेनरों की भरपाई, जहां सामान निर्यात किए जाना है आदि को मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा की आवश्यकता होगी। इस संबंध में, अधिसूचना संख्या 42/2001-सीई (एनटी) से 45/2001-सीई (एनटी) को दिनांक 26.06.2001 जो टर्मिनल उत्पाद शुल्क के भुगतान पर निर्यात एलएफ सामानों के लिए अनुवर्ती प्रक्रिया का विवरण देता है और 19/2004-सीई (एनटी) और 20/2004-सीई (एनटी) दोनों दिनांक 06.09.04 का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

क. निर्यात की प्रक्रिया

3. शून्य रेटेड आपूर्ति (यानी कोई भी निर्यातक) बनाने वाला कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित विकल्पों में से रिफंड का दावा करने के लिए पात्र होगा, अर्थात्: -

(क) वह एकीकृत कर के भुगतान के बिना, अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के भुगतान के बिना, ऐसी शर्तों, सुरक्षा उपायों और प्रक्रिया के तहत निर्धारित किए जाने वाले सामान या सेवाओं के तहत या दोनों बॉन्ड या उपक्रम के पत्र की आपूर्ति कर सकता है; या

(ख) वह करों या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति कर सकता है, एकीकृत शर्तों के भुगतान पर, ऐसी शर्तों, सुरक्षा उपायों और प्रक्रिया के अधीन, माल या सेवाओं या दोनों प्रावधानों के अनुसार प्रदान किए गए इस तरह के कर की वापसी का दावा केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 (धनवापसी) या उसके तहत बनाए गए नियम (यानि केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नियम, 2017)।

4. उपर्युक्त विकल्प (क) के लिए, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नियम, 2017 में धनवापसी दर्ज करने की प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है। अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट की वापसी का दावा करने वाला आयातकर्ता सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक आवेदन या सीधे या जीएसटी आयुक्त द्वारा अधिसूचित एक सुविधा केंद्र के माध्यम से दायर कर सकता है । आवेदन नियमों के अनुसार आवेदन किया जाएगा। धनवापसी के लिए आवेदन केवल निर्यात मेनिफेस्ट या निर्यात रिपोर्ट के बाद, जैसा मामला हो, दायर किया जाएगा, ऐसे सामानों के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 41 के तहत दिया जाएगा। माल के विस्तार के लिए बांड या एलयूटी प्रस्तुत करने के प्रारूपों को सीजीएसटी नियम, 2017 के तहत अलग से अधिसूचित किया गया है। कहा गया प्रारूप आसानी से संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

5. विकल्प (ख) के लिए, व्यापक रूप से प्रक्रिया यह है कि एक पंजीकृत व्यक्ति को निर्यात के लिए माल की आपूर्ति पर भुगतान किए गए एकीकृत सामान और सेवाओं कर की वापसी के लिए कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक निर्यातक द्वारा दायर किए गए जीएसटी चालान विवरण के साथ-साथ शिपिंग बिल को भारत से निर्यात किए गए सामानों पर भुगतान किए गए एकीकृत कर की वापसी के लिए एक आवेदन माना जाएगा और इस तरह के आवेदन को केवल तभी दायर किया जाएगा जब व्यक्ति निर्यात माल को ले जाने वाले वाहन का प्रभारी एक निर्यात पत्र या शिपिंग बिलों की संख्या और निर्यात बिलों की संख्या और निर्यात के बिलों को कवर करने वाली एक निर्यात रिपोर्ट विधिवत करता है और आवेदक प्रारूप जीएसटी - 3 में वैध वापसी प्रस्तुत की है। फॉर्म जीएसटीआर-1 में निहित प्रासंगिक निर्यात चालानों का विवरण कस्टम पोर्टल पर सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाएगा और सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर वापस लौटाएगा, यह पुष्टि चालान द्वारा किए गए सामान भारत से निर्यात किया जाएगा। सामान्य पोर्टल से फॉर्म जीएसटी -3 में वैध रिटर्न प्रस्तुत करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर, सीमा शुल्क प्रणाली धनवापसी के दावे को संसाधित करेगी और प्रत्येक शिपिंग बिल या निर्यात बिल के संबंध में भुगतान किए गए एकीकृत कर के बराबर राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने पंजीकरण विवरण में उल्लिखित आवेदक के बैंक खाते में जमा किया गया। सरकार ने नए जीएसटी कानून के तहत रिटर्न दाखिल करने के लिए रजिस्ट्रनटस को अनुग्रह अवधि की अनुमति दी है। इसलिए, यह धनवापसी प्रक्रिया परिणामस्वरूप ही लागू होगी जब पंजीयक उपर्युक्त रिटर्न फाइल करते हैं। इसके अलावा, निर्यातक विकल्प (क) या विकल्प (ख) का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। धनवापसी आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी।

6. जीएसटी शासन के तहत माल के निर्यात के लिए पहले की प्रक्रिया से सामन्य रूप सुनिश्चित करने के लिए, मौजूदा शिपिंग बिल प्रारूप (मैनुअल / इलेक्ट्रॉनिक दोनों) को आईजीएसटी कानून के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है । शिपिंग बिल के नए प्रारूप पहले से ही लागू किए गए हैं। एआरई -1 प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है जिसमें वस्तुओं के संबंध में वितरित किया गया है, इसके लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

ख . कंटेनरों की सीलिंग।

7. बोर्ड ने पूर्व में कंटेनरों की सील के मुद्दे पर उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क दोनों पर विभिन्न परिसंचरण जारी किए हैं। इन परिपत्रों का एक सारांश और उनमें निपटाए गए विषय मामलों को इस परिपत्र में अनुलग्नक में दिया गया है। वर्तमान में, बंदरगाहों / आईसीडी पर आने वाले कंटेनर की तीन श्रेणियां हैं:

क) सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया के तहत फैक्ट्री परिसर या गोदाम में भरे कंटेनर।

ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की देखरेख में कारखाने परिसर या गोदाम में भरे हुए कंटेनर / मुहरबंद ।

ग) कंटेनर फ्रेट स्टेशन / अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में भरे हुए कंटेनर और मुहरबंद।

8. समानता और व्यापार करने में आसानी के लिए, बोर्ड ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों की देखरेख में अब तक फैक्ट्री स्टफिंग से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। यह एक ट्रस्ट आधारित वातावरण बनाने के लिए बोर्ड का अभिप्राय है जहां मौजूदा कानूनों के अनुसार अनुपालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली और विभाग के खुफिया सेटअप को मजबूत करके सुनिश्चित किया जाता है। तदनुसार, बोर्ड ने कंटेनरों में निर्यात वस्तुओं को भरने और सील करने के लिए एक सरल प्रक्रिया निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

9. सीबीईसी अधिकारियों द्वारा निर्यात वस्तुओं के साथ कंटेनर की सीलिंग को दूर करने का निर्णय लिया गया है। इसके बजाए, निम्नलिखित के अधीन सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया का पालन किया जाएगा |

I क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क अधिकारी निर्यातक परिसर के ब्योरे को सूचित करने का दायित्व होगा कि कारखाना या गोदाम या कोई अन्य जगह जहां कंटेनर स्टफिंग किया जाए।

ii निर्यातक जीएसटी के तहत पंजीकृत होना चाहिए और जीएसटीआरआई और GSTR 2 दर्ज करना होगा। जहां निर्यातक जीएसटी रजिस्ट्रांट नहीं है, वह कंटेनर को भरने और सील करने के लिए निर्यात माल को कंटेनर फ्रेट स्टेशन/ अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में लाएगा। हालांकि, कुछ स्थितियों में, एक निर्यातक सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया का पालन कर सकता है भले ही उसे जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता न हो। इस तरह के अपवाद को इस संबंध में जारी वैध स्टेटस धारक प्रमाण पत्र के तहत डीजीएफटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्टेटस धारकों के लिए उपलब्ध है।

iii इस प्रक्रिया का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी निर्यातक को अपने कारखाने / परिसर से माल के पहले नियोजित प्रवृत्ति से कम से कम 15 दिन पहले अधीक्षक या सीमा शुल्क के मूल्यांकन कर्ता के पद के अधिकार क्षेत्रीय सीमा शुल्क अधिकारी को सूचित करना होगा, फैक्ट्री परिसर या गोदाम से खाद्य पदार्थों का निर्यात करने के लिए सीलिंग प्रक्रिया। अधिकार क्षेत्रीय अधीक्षक या मूल्यांकनकर्ता या सीमा शुल्क निरीक्षक निर्यात के सामान को भरने और बंद करने के लिए वहीं से परिसर में जाएंगे। क्षेत्राधिकारी अधीक्षक या सीमा शुल्क निरीक्षक परिसर में कंटेनर भरने की व्यवहार्यता के संबंध में परिसर का निरीक्षण करेंगे और अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त को एक रिपोर्ट जमा करेंगे या 48 घंटे के भीतर सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त को सूचित करेंगें । अधिकार क्षेत्र के उप आयुक्त / सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त/ आयुक्त स्वीकृत परिसर में सेल्फ-सीलिंग की अनुमति देंगे। एक बार अनुमति मिलने के बाद, निर्यातक स्वीकृत परिसर में स्वयं-सीलिंग किए जाने पर प्रत्येक समय क्षेत्राधिकारिक अधीक्षक या सीमा शुल्क को केवल सूचना प्रदान करेगा। सूचना, इस संबंध में स्वीकृत परिसर, निर्यात वस्तुओं का विवरण और किसी भी प्रोत्साहन पर दावा किया जाता है या नहीं, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

iv जहां कारखाना/ परिसर में भरने की व्यवहार्यता के संबंध में अधीक्षक या मूल्यांकनकर्ता या सीमा शुल्क के निरीक्षक की रिपोर्ट अनुकूल नहीं है, तो एक्सपोटर सामान को सीलिंग उद्देश्यों के लिए कंटेनर फ्रेट स्टेशन / अंतर्देशीय कंटेनर डिपो / बंदरगाह पर लाएगा।

v प्रधान आयुक्त / सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दी गई सेल्फ-सीलिंग अनुमति सभी सीमा शुल्क स्टेशनों पर निर्यात के लिए मान्य होगी। सेल्फ -सीलिंग अनुमति देने वाले सीमा शुल्क गठन निर्यातक के जीएसटीआईएन के साथ सभी कस्टम सदनों / स्टेशनों के साथ अनुमति को परिचालित करेगा ।

vi परिवहन दस्तावेज जीएसटी कानूनों के तहत निर्धारित परिवहन दस्तावेज के समान होगा। एक निर्यातक के मामले में जो जीएसटी रजिस्ट्रांट नहीं है, वहां बिल या परिवहन चालान या लॉरी रसीद परिवहन दस्तावेज होगा।

vii निर्यातक मानक विनिर्देश के छेड़छाड़ सबूत इलेक्ट्रॉनिक-मुहर के साथ कंटेनर सील करेगा। इलेक्ट्रॉनिक मुहर में एक अद्वितीय संख्या होनी चाहिए जिसे शिपिंग बिल में घोषित किया जाना चाहिए। कंटेनर को सील करने से पहले, निर्यातक, आईईसी कोड, जीएसटीआईएन नंबर, माल का विवरण, कर इंवाइस नम्बर, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ई-सील को जोड़ने के लिए) और शिपिंग बिल संख्या जैसे डेटा को खिलाएगा इलेक्ट्रॉनिक मुहर इसके बाद, परिसर छोड़ने से पहले कंटेनर को उसी इलेक्ट्रॉनिक मुहर से सील कर दिया जाएगा।

viii निर्यातक स्व-निकासी पर निर्यात माल को साफ़ करने का इरादा रखता है (सीमा शुल्क ब्रोकर को नियोजित किए बिना) डिजिटल हस्ताक्षर के तहत शिपिंग बिल दर्ज करेगा।

ix. स्व-मुहरबंद कंटेनरों में सभी सामान निर्यात के बंदरगाह पर परीक्षा / निरीक्षण के लिए जोखिम आधारित मानदंड और खुफिया, यदि कोई हों । बंदरगाह / आईसीडी में मामले में, सीमा शुल्क अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक मुहरों की अखंडता को सत्यापित करेगा ताकि किसी भी तरह के छेड़छाड़ की जांच हो सके। जोखिम प्रबंधन सिस्टम (आरएमएस) को हस्तक्षेप / परीक्षा मानदंडों को सुधारने के लिए उचित रूप से संशोधित किया जा रहा है। हालांकि, परीक्षा / स्कैनिंग के लिए ऐसे कंटेनरों के यादृच्छिक या खुफिया आधारित चयन जारी रहेगा।

10. केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड ने निर्णय लिया है कि कंटेनरों की सील के संबंध में उपर्युक्त संशोधित प्रक्रिया 01.09.2017 से प्रभावी होगी। भविष्य की तारीख निर्धारित की गई है क्योंकि 10.09.17 तक जीएसटी के तहत रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है और हितधारकों को नई प्रक्रियाओं के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से भी। इसलिए, सुविधा के एक उपाय के रूप में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर्यवेक्षण के तहत बोतल मुहर के साथ कंटेनर को सील करने का मौजूदा अभ्यास या अन्यथा जारी रहेगा। मौजूदा परिपत्र 01.09.2017 को इस परिपत्र में दिए गए संशोधित निर्देशों के विपरीत संशोधित किया जाएगा।

(बंदना देवरी)
आयुक्त

C.No. VIII (48)~~09~~23/CUS/TECH/~~MISC~~/~~EXP-IMP~~/2018/ LOFSP/15518-536(A) dated 4 JUL 2017

प्रति सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु ।

1.मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं सीमा शुल्क,शिलांग ।

2.आयुक्त , सी जीएसटी आयुक्तालय , अगरतला / आइजल /दिमापुर/ डिब्रूगढ़/गुवाहाटी/ इम्फाल/ ईटानगर/शिलांग ।

3. उप आयुक्त /करीमगंज /इम्फाल /गुवाहाटी /दिमापुर/धुबरी/आइज़ल /सहायक आयुक्त सीमा शुल्क प्रभाग अगरतला / शिलांग उनसे अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में सभी व्यापारी / निर्यातकर्ता/ आयातकर्ता /संघ को इस जन सूचना द्वारा सूचित कर एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे ।

3 अधीक्षक, कंप्यूटर कक्ष, सीमा शुल्क मुख्यालय, शिलांग को इस स्थायी आदेश को आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करे ।

.4 गार्ड फाइल

(बंदना देवरी)
आयुक्त